भारत सरकार
योजना मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 212
दिनांक 02.02.2022 को उत्तर देने के लिए

पंचवर्षीय योजना

212. श्री कल्याण बनर्जी:

क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नीति आयोग ने 2017 से, 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद, सरकार के पारदर्शी और वस्तुपरक तंत्र के विकास के लिए व्यापक पंचवर्षीय योजना बनाना बंद कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इसमें तत्कालीन योजना आयोग से 12वीं पंचवर्षीय योजना रिपोर्ट (2012-17) प्राप्त हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संरचना को बंद करने के क्या कारण हैं एवं देश के समग्र विकास के लिए योजना की वर्तमान रूपरेखा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय;
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) योजना मंत्रालय एवं
राज्यमंत्री (कारपोरेट कार्य मंत्रालय)

(राव इंद्रजीत सिंह)

(क) राष्ट्रीय उद्देश्यों के आलोक में राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं, क्षेत्रों और कार्यनीतियों का एक साझा विज़न विकसित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने 01 जनवरी, 2015 से योजना आयोग को नीति आयोग में परिवर्तित कर दिया है। नीति आयोग कृषि, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, शिक्षा, स्वास्थ्य-सेवा, जल संसाधन, शहरीकरण, ऊर्जा और परिवहन आदि जैसे क्षेत्रों में केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों को निर्देशात्मक और नीतिगत इनपुट प्रदान करता रहा है। नीति आयोग की स्थापना के साथ ही 12वीं योजना के बाद पंचवर्षीय योजनाओं की प्रक्रिया बंद कर दी गई है।

(ख) और (ग) जी, हां। 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) का मूल्यांकन 08 फरवरी, 2015 को नीति आयोग की शासी परिषद की पहली बैठक में लिए गए निर्णय के उपरांत किया गया था। इस मूल्यांकन में प्रथम चार वर्षों (2012-13 से 2015-16) के दौरान प्रदर्शन का आकलन किया गया और राष्ट्र के विकास एजेंडे को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से नीति-या-कार्यान्वयन संबंधी मुद्दों की व्याख्या की गई। इसके अलावा, एक उत्तरोत्तर खुली और उदार अर्थव्यवस्था की पृष्ठभूमि में, यह महसूस किया गया कि देश के लिए दीर्घकालिक विज़न के साथ विकास प्रक्रिया के लिए एक नए दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इस संदर्भ में, नीति आयोग ने विकास, अवसंरचना, समावेश और शासन के कारकों सहित 41 प्रमुख क्षेत्रों में नीतिगत सिफारिशों के साथ नव भारत @75 हेतु कार्यनीति दस्तावेज जारी किया है। इसके अलावा, नीति आयोग द्वारा वर्ष 2017-18 से 2019-20 के लिए एक तीन वर्षीय कार्य योजना भी जारी की गई।

*****